Agriculture Institutes under IARI, Orissa

2659. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of research centres and projects under the Indian Council of Agriculture Research in Orissa, location wise;

(b) the details of the funds allocated and expenditure incurred by the Government on each of them during each of the last three years, project wise;

(c) the details of the achievements made by them; and

(d) the impact thereof on the Agricultural production in the State during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The names of research centres and projects under Indian Council of Agricultural Research in Orissa, location-wise and the details of funds allocated and expenditure incurred by the Government on each of them during last three years, project-wise are given in Annexure. [*See* Appendix 186, Annexure No. 55]

(c) and (d) The details of achievements and the impact thereof on the agricultural production in the State during last three years are given in Annexure. [*See* Appendix 186, Annexure No. 55]

मक्का योजना

2660. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से एक विशेष मक्का योजना लागू की गई थी और इसके परिणामस्वरूप 15.43 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन हुआ था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रदेश सरकार के चार और जिलों बुलन्दशहर, देवरिया, बहराईच और ललितपुर के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की राशि वाली एक अनुदान योजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकार की सहायता से कोई विशेष मक्का योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में मक्का की संभावना वाले सभी जिलों में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1995-96 में इसके आरंभ से ही चल रही है तथा इसके परिणामस्वरूप 1997-98 में इस राज्य में मक्का की 15.43 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उपज हुई थी।

(ख) और (ग) इन चार जिलों के लिये "संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मक्का आधारित फसल प्रणाली में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम" नामक उप-कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार (कृषि निदेशालय) से 99,29,625/- रुपये की धनराशि के लिये एक प्रस्ताव मिला था।

बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सभी संबंधित तीन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मक्का से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार के लिये 3,43,26,380/-रुपये (814,000/- अमेरिकी डालर) की कुल लागत से "भारत में मक्का आधारित फसल प्रणाली" पर एक उप-कार्यक्रम, जिसके लिये धन व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की जाएगी, पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा उप-कार्यक्रम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद इस उप-कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरंभ होगा।

Food Production in Assam

2661. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the target fixed for foodgrains during the ninth five year plan in Assam;

(b) the details of measures proposed to be taken by Government to increase foodgrains production during this plan period; and

(c) the details of investment proposed to be made in the production of foodgrains in the State of Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The targets of foodgrains production proposed by Government of Assam for Ninth Five Year Plan are as under:-

(Production in lakh tonnes)

Crop	Target
Rice	43.30
Wheat	1.00
Maize and other cereals	0.25
Pulses	1.05
TOTAL FOODGRAINS	45.60

(b) Government of India supplements state efforts through Centrally Sponsored Schemes for increasing foodgrains production.

(c) In Assam State under crop Husbandry the approved outlay is Rs. 423.40 crore for Ninth Five Year Plan.

सूखे से प्रभावित लोगों के लिए सहायता

2662. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन अध्ययन के अनुसार गुजरात में सूखा-प्रवण जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य को वर्ष-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सूखे से प्रभावित लोगों को मकानों के निर्माण के लिए कितनी सहायता दिए जाने का विचार है जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 1.4.99 की स्थिति के अनुसार किसी भी जिला या तालुका में सूखा/अभाव की स्थिति नहीं है।

(ख) राज्य सरकार से, सूखे सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष के तहत वार्षिक आवंटन से राहत व पुनर्वास उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। गत 3 वर्षों के दौरान आपदा राहत कोष के तहत गुजरात के लिये आबंटन केन्द्रीय अंश तथा राज्य अंश का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
1996-97	139.60	104.70	34.90
1997-98	147.31	110.48	36.83
1998-99	154.83	116.12	38.71

राज्य सरकार ने अभाव से संबंधित क्रियाकलापों के लिये प्रभावित जिलों को 1996-97 में 52.83 लाख रुपये, 1997-98 में 104.34 लाख रुपये तथा 1998-99 में 20.40 लाख रुपये आबंटित किये थे।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह सूखे से प्रभावित लोगों के लिये घरों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध नहीं कर रही है।

Hormone Injection to Increase Milk Production

2663. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are permitting injecting milch animals with bovine growth harmone (BGH) to increase the milk output;

(b) if so, how the adverse side effects on milch animals generated by this type of injections would be avoided; and

(c) whether the Research study conducted by DAV Research society in this regard has been ignored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.